[2011] 10 एस.सी.आर 739

रघुवीर सिंह

बनाम

राजस्थान राज्य व अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 82–83/2005)

29 अगस्त, 2011

(हरजीत सिंह बेदी एवं ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायमूर्तिगण)

दंड संहिताए 1860 ए द धारा 302 जमीन पर विवाद के कारण हत्या . विवाद यह था कि जमीन पर किसका कब्जा थाए शिकायतकर्ता पक्ष आरोपी था। शिकायतकर्ता पक्ष ने उक्त भूमि को जोतना शुरू कर दिया. आरोपी पक्ष ने भी वहां पहुंच कर जुताई शुरू कर दी.मारपीट हुई. दोनों पक्षों को चोटें आईं। आरोपी 'के' ने पीड़ित पर हथियार से हमला कर किया– जिससे उसकी मौत हो गईए अन्य आरोपियों ने भी शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया . ट्रायल कोर्ट डी ने 'के' सहित 09 आरोपियों में से 7 को दोषी ठहराया अन्तर्गत धारा 302, 302 ध्149, 307, 307 ध्149 उच्च न्यायालय ने 'के' के दोषसिद्धी को धारा 304 भाग द्वितीय में संशोधित कियाए तीन अन्य अभियुक्तों को दोषसिद्धी को क्रमशः धारा 324 और एक अन्य अभियुक्त की धारा 325 में संशोधित किया गया . अपील पर माना गयाः गवाहों द्वारा पीड़ित को लगी चोट के लिए आरोपी 'के' को जिम्मेदार ठहराया गया था. चिकित्सा साक्ष्य से साबित हुआ कि उक्त चोट आरोपी 'के' द्वारा इस्तेमाल किए गये हथियार से थी और चोट की सीमा और गंभीरता से पता चला कि आरोपी 'के' पीड़ित की मृत्यु का इरादा था. साक्ष्य से यह भी पता चला कि उक्त चोट सामान्य प्रकृति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी . अन्य तीन आरोपियों को लगी चोटें सामान्य प्रकृति की थी और यह नहीं कहा जा सकता कि यही कारण था मौत का. इसलिए आरोपी 'के' को पीड़ित की हत्या के लिए धारा 302 भाण्दंण्संण् के तहत दोषी ठहराया गया और ट्रायल कोर्ट के फैसयले को उस सीमित सीमा तक बहला किया गया. अन्य आरोपियों की अपील खारिज कर दी गई। आपराधिक कानून. पकड़े गए आरोपी को लगी चोटों का स्पष्टीकरण. आरोपी को लगी प्रत्येक चोट को समझाने की आवश्यकता नहीं है और विशेष रूप से जहां सभी चोटें अभियुक्त को लगी चोटें सामान्य प्रकृति की है। मामले के तथ्यों का आकलन

सम्भावनाओं की प्रकृति के आधार पर किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, अभियुक्त को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाह ने एक भी शब्द नहीं बोलाए उनके द्वारा उन्हें किस प्रकार पीड़ित किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण मेंए बचाव पक्ष वैध रूप से यह संदेह पैदा कर सकता है कि घटना की उत्पवत्ति रहस्य में डूबी हुई थीए निःसन्देह, बड़ी संख्या में गवाह थेए उनमें से कुछ गम्भीर रूप से घायल थे। अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए, लेकिन तत्काल मामले मेंए यह तथ्य स्वंय आरोपी को यह दावा करने से नहीं रोक सकता कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया था।

बी. दोषीसिद्धी के विरूद्ध अपील उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति. अनुच्छेद. 136 के तहत हस्तक्षेप का दायरा माना गयाए यदि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोंण प्रसंशनीय या सम्भव थाए तो उच्चतम न्यायालय के लिए दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। विभिन्न परिस्थितियां जब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करेंगा . भारत का संविधान 1950, अनुच्छेद 136 । अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जिस भूमि पर घटना घटी थीए वह घटना की तारीख में कई साल पहले अपीलकर्ता. पीण्डब्ल्यू 1 के पास गिरवी रखी गयी थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिनए पीण् डव्ल्यूण् 1 पीड़ित मृतक व अन्य लोगों के साथ जमीन की जुताई कर रहा थाए तभी एक आरोपी दो ट्रैक्टरों पर उस स्थान पर पहुंचा और उसी जमीन को जोतना शुरू कर दिया। इस पर पीण्डब्ल्यूण्1 ने विरोध कियाए जिस पर आरोपियों ने उसे अपने ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। इस बीचए फरसियोंए लाठियोंए टाचियाए दांतियों से लैस अन्य आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया और अपने ट्रैक्टरों से पीड़ित को कुचल दिया और जब पीण्डब्ल्यूण्1 ने बचाने का प्रयास किया तो उस पर भी अपने हाथों से बार किया। ट्रायल कोर्ट ने 09 आरोपियों में से 07 को भाण्दंण्संण् की धारा 302 ए 302 ध् 149 ए 307 ए 307 ध् 149 के तहत दोषी ठहराया।

दोषी अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। अपीलकर्ता पीण् डब्ल्यू 1 ने इसके खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया। दो आरोपियों को बरी कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने माना कि जिस भूमि पर घटना घटी व वन विभाग की थी और आरोपियों के खेतों से सटी हुई थी तथा शिकायतकर्ता पक्ष उस दिन पहली बार उक्त भूमि पर खेती करने गया थाए हालांकि पटवारी ने ऐसा किया था। उन्हें ऐसा न करने की सलाह दीए इसमें आगे कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया और यह पाया गया है कि शिकायतकर्ता पक्ष ने इसमें अतिक्रमण किया था और जुताई शुरू कर दी थीए जिस पर खुली लड़ाई हुई और दोनों पक्षों के लोगों के चोटें आयीं। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मामले को देखते हुए धारा 147 ए 148 और 149

प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक आरोपी को उसके व्यक्तिगत कृत्य के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए । तद्नुसार अभियुक्तों की सजा को संशोधित किया गया। आरोपी 'के' धारा 302 ए 302 ध्149 ए 307 ए 307 ध्149 भाण्दंण्संण् के तहत दोषसिद्धी को रद्द कर दिया गयाए इसके बजाये उसे भाण्दंण्संण् की धारा 304 भाग द्वितीय के तहत दोषी ठहराया गया। भाण्दंण्संण् की धारा 302 ए 302 ध्149 ए 307 ए 307 ध्149 भाण्दंण्संण् के तहत 'ए'ए 'एस'ए 'एम' की दोषसिद्धी को रद्द कर दिया गयाए हालांकि भाण्दंण्संण् की धारा 324 के तहत उसकी सजा की पुष्टि की गई। धारा 302 ए 302 ध्149 ए 307 ए 307 ध्149 भाण्दंण्संण् के तहत 'का' की दोषसिद्धी को रदद कर दिया गयाए हालांकि धारा 325 भाण्दंण्संण् के तहत उनकी सजा की पुष्टि की गई। ''आर'' की अपील स्वीकार कर ली गई और उसे बरी कर दिया गया। अपील के लम्बित रहने के दौरान एक आरोपी ''आर के'' की मृत्यु हो गयी और उसके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई। तत्काल अपीले राज्य के साथ साथ पीण्डब्ल्यूण्1 द्वारा भी दायर की गई।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुएः.

मानाः 1. यदि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोंण प्रसंशनीय या सम्भव था तो बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए उन परिस्थितियें में उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करेगाए जब ;पद्ध उच्च न्यायालय का निर्णय स्थापित कानूनी स्थिति की अनदेखी करके कानून के पूरी तरह से गलत दृष्टिकोंण पर आधारित होए ;पपद्ध उच्च न्यायालय की एक निष्कर्ष रिकार्ड पर मौजूद साक्षों और दस्तावेजों के विपरीत हैए ;पपपद्ध सबूतों में से निपटने में उच्च न्यायालय का पूरा दृष्टिकोंण स्पष्ट रूप से अवैध थाए जिससे न्यायालय की गम्भीर हानि हुई। ;पअद्ध मामले के रिकॉर्ड पर गलत काम और तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित हैए ;अद्ध सर्वोच्च न्यायालय को हमेशा उच्च न्यायालय के निष्कर्षो को उचित महत्व और विचार देना चाहिए। ;अपद्ध सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने में बेहद अनिच्छुक होगा जब सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने बरी करने का आदेश दर्ज कर लिया हो। हालांकि यह परिस्थितियां उदाहरणात्मक है और सम्पूर्ण नहीं। उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप इन मापदण्डों पर आधारित होना चाहिए। मौजूदा मामले मेंए अभियुक्तों की चोटों के बारे में नहीं बताया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाह ने एक शब्द नहीं कहा कि उन्हें किस तरह की चोटें लगी थी। मामले के इस दृष्टिकोणं मेंए बचाव पक्ष वैध से यह संदेह पैदा कर सकता है कि घटना की उत्पति रहस्यमय डूबी हुई थी और अभियोजन पक्ष ने कार्यवाही के एक हिस्से को दबा दिया था। यह सच है कि किसी आरोपी को लगी प्रत्येक चोट को समक्षा ने की आवश्यकता नही है और विशेष रूप से जहां आरोपी को लगी

सभी चोट साधारण प्रकृति की है ;जैसा की वर्तमान मामले मेंद्ध और मामले की तत्वों का आकलन करना होगा संभावनाओं की प्रकृति मौजूदा मामले में चोटें एफ थीए इसकी व्याख्या करना जरूरी था क्योंकि जिस जमीन पर घटना घटी थी उस पर कब्जे को लेकर गंभीर विवाद थाए खासतौर पर इसलिए क्योंकि पीण्डब्लूण् 01 खुद कब्जे की प्रकृति के बारे में अनिश्चित था। रिकोर्ड पर बयान और पटवारी ने शिकायर्ता पक्ष जी को भूमि में अतिक्रमण ना करने की चेतावनी भी दी थी। निस्संदेह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए बडी संख्या में घयल गवाह थेए उनमें से कुछ गंभीर रूप से घयल थेए लेकिन उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के आलोक में कि एच के कब्जे के बारे में अनिश्चितता थीए यह तत्थ अपने आप में इंकार नही कर सकता है। आरोपियों ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता घायल गवाहों में से एकए पीण्डब्लू 03 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया था कि झगडा अचानक हुआ था और दोनों प्रतिद्वंद्वी समूह कह रहे थे कि वे जमीन बोयेगे। इस कथन को जांच अधिकारी पीण्डब्लूण् 17 के साक्ष्य द्वारा भी समर्थित किया गया थाए जिन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि पटवारी के अनुसारए लडाई उस भूमि पर हुई थी जो ताजा थी और एक 'जी' और 'डी' से संबंधित थी और यह कि जमीन शिकायर्ता के पक्ष में थी यह बयान अन्य गवाह विशेषकर पीण्डब्लू 01 के साक्ष्य से भिन्न था क्योकि उसने कहा था कि वे लगभग 20 बीस वर्षों से विचाराधीन भूमि पर कब्जा कर रहे थे। घटना स्थल को लेकर भी संशय बना हुआ है। पीण्डब्लूण् 01 के घर से शव और कलटीवैटर बरामद किया गया। पीण्डब्लूण् 17 ने स्वीकार किया कि घटना स्थल से खून से सनी कोई मिट्टी नही उठाई गई। तत्थों के आलोक में यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी के दोनों पक्ष लडाई करने आये थेए उचित प्रतीत होती हैए क्योंकि यह साक्ष्यों की सराहना पर एक आकलन थाए जिसे स्पष्ट रूप से गलत नहीं कहा जा सकता है इस न्यायालय के हस्तक्षप को आमंत्रित करने के लिए गजानंद के मामले में ई का अवलोकन की मामले को एक स्वतंत्र लडाई के मामले के दायरे में लाने के लिए दोनो पक्षों को सशस्त्र सहित आना होगा और लडाई के लिए तैयार रहना होगाए वर्तमान मामले में इस प्रणाम के साथ लागू किया जाना चाहिए कि प्रत्येक आरोपी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। ; पैरा 5 द्ध ;750.ई.एचः 751.ए.एचः 753 ए.एचः एफ 753.एद्ध

गजानंद एवं अन्य। बनाम यूपी राज्य एआईआर 1954 एससी 695 . पर निर्भर।

भंवर सिंह एवं अन्य। बनाम मण्प्रण् राज्य ;2008द्ध 16 एससीसी 657ः2008 ;15द्ध एससीआर 879. अनुपयुक्त ठहराया गया।

यूपी राज्य बनाम बन्ने ;2009द्ध. 4 एससीसी 271 . संदर्भितं

कल्टीवेटर से लगी चोट चोट नंबर 1 थी जो एच घातक चोट थी और गवाहों द्वारा इसका कारण बताया गया था 'के' कोए यह तर्क इस कहानी पर विश्वास नही किया जा सकता कि किसान को पहले उठाया गया था और फिर पीडित पर गिरा दिया गया था क्योंकि पीण्डब्लूण् 01 में अपने साक्ष्य में इस तत्थ का उल्लेख नहीं किया गया थाए हांलाकि अन्य गवाहों ने बी ने ऐसा किया था और इस तरहए यह कहानी असंभव थीए हांलाकि यह मान भी लिया जाये कि कल्टीवेटर को उठाया नही गया था और फिर गिराया गया थाए फिर भी कल्टीवेटर से चोट नंबर 01 लगी थीए यह चिकित्सीय साक्ष्य से स्पष्ट था और चोट की सीमा और गम्भीरता से पता चलता है कि आरोपी 'के' का इरादा ऐसा करने का था। पीड़ित की मृत्यु का कारणए साक्षियों से यह भी स्पष्ट थाए कि चोट संख्या 01 प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। अन्य तीन आरोपियों को लगी चोटें सामान्य प्रकृति की थी और किसी भी कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता कि यही मौत का कारण थी। इस तथ्य के प्रकाश में कि डी का तत्काल मामला एक स्वतंत्र लड़ाई का हैए आरोपी 'ए'ए 'एम' और 'आरके' को उनकी सम्बन्धित चोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हालांकिए जब मामला उच्च न्यायालय में था तब 'आरके' की मृत्यु हो गयी। इसलिए जहां तक आरोपी 'के' का सबाल हैए उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्षें पर भी ई भाण्दंण्संण् की धारा 304 भाग द्वितीय के तहत उसकी सजा गलत थी। आरोपी 'के' को पीड़ित की हत्या के लिए भाण्दंण्संण् की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाता है और उस सीमित सीमा तक ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल किया जाता है। जहां तक अन्य आरोपियों का सम्बन्ध हैए उच्च न्यायालय के एफ आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। ;पैरा 6 द्ध ;753. एच.754.ए.एफद्ध

केस कानून संदर्भः.

एण्आईण्आरण् 1954 एससी 395	पर भरोसा	पैरा 4 ए 5
2008 ;15 द्ध एससीआर 879	को अनुपयुक्त	पैरा 4 ए 5
;2009 द्ध 4 एससीसी 271	के लिए भेजा	पैरा 4

क्षेत्राधिकार में संदर्भित किया गया हैः 2005 की आपराधिक अपील एच संख्या 82.83।

डीण् बीण् में जयपुर खण्डपीठए जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनाक 10.09.2003 से। 1998 की आपराधिक अपील संख्या. 796 और डीण्बीण् करोड़। 1999 की पुर्नयाचिका संख्या. 188

सीण्आरण्एलण् 2005 की अपील संख्या.778

डा0 मनीष सिंघवीए एण्एण्जीण्ए अनीथा शेनोईए रश्मि नानन्द कुमारए अंसार अहमद चोधरीए विभा भट्ट मुखीजाए लीमा दत्तए विजय वर्माए मिलिन्द कुमारए अरूणेश्वर गुप्ता पक्षों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

हरजीत सिंह बेदीए जेण्1 ण् यह निर्णय 2005 की आपराधिक अपील संख्या 82.83 और 778 का निपटारा करेगा। तथ्य 2005 की आपराधिक अपील संख्या 778 के लिए है।

2. अभियोजन की कहानी के अनुसारए पीण्डब्ल्यूण् प्रभू कोली और उसके भाईयों ने घटना से कई साल पहले खसरा नम्बर 250 वाली पॉच बीघा जमीन पीण्डब्ल्यूण्1 रघवीरसिंह को गिरवी रख दी थी। दोपहर करीब दो बजे 07 अगस्त 1997 कोए रघुवीर ई सिंहए छोटे लाल के साथ। जब आरोपी राजेन्द्रए मुन्शी और गिरधारी जमीन जोतने का काम कर रहे थे। कल्लूए कमरूए तैयव और रहमत दो ट्रैक्टरों से वहां पहंचे और उसी जमीन को जोतने भी लगेए रघुवीरसिंह ने इस घुसपैठ का विरोध कियाए जिस पर उन्होंने अपने ट्रैक्टरों से उसे कुचलने का प्रयास किया। इसी बीच असुद्दीनए महबूबए मौजए सोहनलाल और कमरू ने फारसियोंए टाचियां दातियां और लाठी डण्डों से लैस होकर उन पर हमला बोल दिया और जहां मौज और असुद्दीन ने गिरधारी के सिर पर दांती और टाचियां से वार कर दियाए वहीं कल्लू और रहमत ने उसके ऊपर हमला कर दियाए असुद्दीन तैयव और कमरूददीन ने भी अपने हाथो से उन पर हमला कर दिया। गिरधारी की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि छोटे लालए लल्लूए राजेन्द्र और मुन्शी गम्भीर रूप से घायल हो गये। इसके बाद रघुवीरसिंह पलिस थाना शाम 5.30 बजे गये। थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई। उसी दोपहर और उसी के आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई। जांच पूरी होने परए आरोपियों पर भाण्दंण्संण् के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाये गयेए जिसमें अन्य बातों के साथ साथ धारा 302 और 302 ध्149 ए 307 ए 307 ध्149 शामिल थे। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में सबूतों पर विश्वास किया। कुल 17 उ गवाहों में सेए प्राथमिक गवाह पीण्डण्1 रघुवीरसिंह प्रथमए मुखबिरए पीडब्ल्यूण्2 राजेन्द्र कुमारए पीडब्ल्यू 3 छोटै लालए पीडब्ल्यू 4 मुन्शीरामए पीडब्ल्यू 5 लल्लूरामए पीडब्ल्यू 6 सुरेश कुमार और पीडब्ल्यू 7 थानसिंह। अभियोजन पक्ष ने पीडब्ल्यू 14 डा0 संजय गुप्ता के बयान पर भी भरोसा कियाए जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया था और उसमें पांच चोटें पायीं थी और उपरोक्त पांच गवाहों में से भी पूछताछ की थी। रघुवीर सिंहए राजेन्द्र कुमारए छोटे लालए मुन्शी और लल्लू कई चोटें मिलीए जिनमें से कुछ गम्भीर प्रकृति की थीए जबकि आरोपी तैयव की ओर से

कल्लूए रहमतए असुद्दीन और कमरू घायल पाये गये। साधारण चोटों के साथ ण्दंण्प्रण्संण् की धारा 313 के तहत दर्ज किये गये उनमें बयानों में। आरोपियों ने सीधे तौर पर अपनी संलिप्तता से इन्कार किया। उन्होंने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया। ट्रायल कोर्ट में उपरोक्त चश्मदीद गवाहों के बयान और मेडिकल सबूतों पर भरोसा करते हुए 09 आरोपियों को भाण्दंण्संण् की धारा 302 और 302 ध्149 ए 307 ए 307 ध्149 आदि के तहत दोषी ठहराया और उन प्रावधानों के तहत कारावास की विभिन्न शर्तो की सजा सुनाई। हालांकि विचाराधीन न्यायालय में महबूब खान और तैयव को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराये गये सात अभियुक्तों ने 1998 की डीबी आपराधिक अपील संख्या 796 दायर करके उनकी सजा को चुनौती जबकि शिकायतकर्ता पीडब्ल्यूण् रघुबीर ने डीबी दायर करके महबूत खानए तैयव खान को बरी करने का विरोध किया। 1999 का आपराधिक पुर्नरीक्षण संख्या 188। उच्च न्यायालय में जी अपील के लम्बित रहने के दौरान रहमत का निधन हो गया और उसके खिलाफ कार्यवाही को समाप्त होने के रूप में निपटाया गया। साक्ष्य पर पुर्नविचार करने पर उच्च न्यायालय आया। यह निष्कर्ष कि जिस भूमि पर घटना हुई थी वह प्रभू से सम्बन्धित नहीं थाए लेकिन वास्तव में वन विभाग से सम्बन्धित था और आरोपी मौज रघुवीर सिंह के खेतों से सटा हुआ था। खान और रहमत और शिकायतकर्ता पक्ष ने दुर्भाग्यपूर्ण दिनए पहली बार उक्त भूमि पर खेती करने के लिए चला गयाए हालांकि पटवारियों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी। अदालत ने यह भी पाया कि आरोपी के कब्जे में प्रतीत होता है कहा गया भूमि और यह पता लगाना कि शिकायतकर्ता पक्ष ने अतिक्रमण किया था इसमें और जुताई शुरू कर दी थी जिस पर विरोध दर्ज कराया था एक स्वतंत्र लड़ाई हुई थी और दोनों पक्षों के लोगों ने उन्हें चोटें आईं जिन पर कल्लू आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। अदालत ने तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि मामले के इस दृष्टिकोण मेंए धारा 147 ए 148 और 149 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया जा सका और प्रत्येक अभियुक्त को उत्तरदायी और जिम्मेदार ठहराया जाना था अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए। उच्च न्यायालय ने तदनुसार जांच की प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका और यह देखा कि हालांकि कल्लू पर आईण् पीण् सीण् की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया था गिरधारी की पीठ के बाईं ओर घातक चोटकिसान उसके ऊपर से भागकर उसकी मौत का कारण बनने का इरादा नहीं था और इसलिए वह आईण् पीण् सीण् की धारा 304 भाग प्प् के तहत उत्तरदायी होगा। न्यायालय ने तदनुसार अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को निम्नानुसार संशोधित किया:

;पद्ध ष् अपीलार्थी रहमुद्दीन की अपील को अनुमति दी जाती है और धारा 302 ध्149 के तहत आरोपों से बरी किया जाता हैए 447 ए 147 ए 325 ध् 149 ए 324 ध् 149 और 323 ध्149

आईण् पीण् सीण्। वह है। जमानत परए उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है और उसके जमानत बांड पदमुक्त हो जाएँ।

; ;खद्ध अपीलार्थी रहमत खान की मृत्यु के दौरान अपील की विचाराधीनताए उसके खिलाफ कार्यवाही हटा दी गई है।

; पपपद्ध अपीलार्थियों कल्लूए असदुद्दीनए सोहन लाल की अपील कमरुद्दीन और मौज खान को आंशिक रूप से अनुमति है। अपीलार्थी कल्लू को धारा के तहत दोषसिद्धि 302 ए 447 ए 148 ए 325 ध् 149 ए 324 ध् 149 और 323 ध्159 को अलग कर दिया जाता हैए इसके बजाय उसे धारा 304 के तहत दोषी ठहराया जाता है। भाग प्प् आईण् पीण् सीण् जैसा कि वह एक के लिए कारावास में था छह साल से अधिक की अवधिए न्याय का अंत ख्2011, 10 एसण् सीण् आरण् 748 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट उसे पहले से ही अवधि के लिए सजा देने में पूरा किया जाए कारावास में उसके द्वारा पीड़ितए कल्लूए जो जेल में हैए यदि आवश्यक नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। कोई अन्य मामला।

; पअद्ध अपीलार्थियों सोहन लालए मौज खान और असदुद्दीन को धारा 305 ध्149 के तहत दोषी ठहराया जाना। और 323 ध्149 अलग रखा गया है और वे हैं उक्त आरोपों से बरी। हालाँकि आईण् पीण् सीण् की धारा 324 के तहत उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई है और उन्हें पहले से गुजर चुकी अवधि के लिए सजा दी जाती है उनके द्वारा कैद में। सोहन लाल और मौज खान जमानत पर हैंए उन्हें आत्मसमर्पण करने और जमानत लेने की आवश्यकता नहीं है बांडों का निर्वहन किया जाता है। अपीलार्थी असदुद्दीनए जो जेल में हैए उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगाए यदि नहीं किसी भी अन्य मामले में आवश्यक।

;अद्ध अपीलार्थी कमरुद्दीन को धाराओं के तहत दोषसिद्धि 302 ध् 149 ए 447 ए 148 ए 324 ध् 149 और 323 ध्149 को अलग कर दिया जाता है और वह उक्त आरोपों से बरी हो जाता है। बिनि। हालाँकि आईण् पीण् सीण् की धारा 325 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि हो गई है और उसे उस अवधि की सजा सुनाई गई है जो वह पहले ही कारावास में बिता चुका है। वह चालू है। जमानतए उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है और उसके जमानत बांड खड़े हैं छुट्टी दे दी।

; अपद्ध क्ण्ठण्ब्तपउपदंस संशोधन छवण्188 ध्1999 शून्य है। योग्यता खारिज हो जाती है।

; अपपद्ध विद्वत विचारण न्यायाधीश का विवादित निर्णय ऊपर बताए अनुसार संशोधित किया गया है ष्।

3 ण् महबूब खान और तैयब खान को बरी करने का फैसला था हालाँकिए इस याचिका पर कहा गया कि नेत्र संबंधी गवाही की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा नहीं की गई थी। इस स्थिति में राज्य द्वारा भी वर्तमान अपील दायर की गई है। जैसा कि पीडब्लू.1 रघुवीर सिंह ने किया।

4 ण् हमने डॉण् मनीष सिंघवीए विद्वान रघुबीर सिंह बनाम को सुना है।

राजस्थान राज्य और ओआरएस। ख् हरजीत सिंह बेदीए जे।,

राजस्थान राज्य की अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्रीण् अनीथा शेनॉयए रघुवीर सिंह की विद्वान वकीलए और सुश्री विभा दत्ता मखीजा भी विद्वान न्यायमित्र अभियुक्त उत्तरदाता। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने हमारे सामने कई तर्क रखे हैं। सबसे पहले यह बताया गया है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि घटना प्रभु के खेत में हुई थी जो रघुवीर सिंह और अभियुक्तों के साथ गिरवी रखा गया था इसलिए हमलावरों ने उस क्षेत्र में अतिक्रमण किया था और एक स्वतंत्र लड़ाई का निष्कर्ष गलत थाए विशेष रूप से अभियोजन पक्ष का मामला एक बड़े के बयानों पर आधारित था गंभीर रूप से घायल प्रत्यक्षदर्शी की संख्या। यह हो चुका है इस बात पर जोर दिया कि एक स्वतंत्र लड़ाई ने माना कि दोनों पक्षों के पास था युद्ध करने के लिए आएंए जैसा कि इस न्यायालय ने गजानंद और ओआरएस में कहा था। बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य एण् आईण् आरण् 1954 एसण् सीण् 695 और भंवर सिंह और अन्य। बनाम। एमण् पीण् राज्य ;2008द्ध 16 एसण् सीण् सीण् 657 और के आलोक में यह तथ्य कि अभियुक्त हमलावर थेए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह से गलत था। यह भी प्रस्तुत किया गया है विद्वान वकील द्वारा कि यह मानते हुए भी कि एक मुक्त था लड़ाई के आरोपी असदुद्दीनए मौज खानए कल्लू और रहमतए किसी भी मामले मेंए आईण् पीण् सीण् की धारा 303 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी थे। क्योंकि उन्होंने मृतक गिरधारी को चोट पहुँचाई थी। सुश्रीण् हालाँकिए अभियुक्त के विद्वान वकील मखीजा ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया है और एक मुद्दा उठाया है प्रारंभिक तर्क है कि इस तरह में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप मामलों को न्यूनतम होना आवश्यक था और यदि उच्च न्यायालय ने एक दृष्टिकोण लिया जो सबूत पर संभव थाए हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध मेंए विद्वान वकील नेयूण् पीण् बनाम राज्य पर निर्भर बाने ;2009द्ध 4 एसण् सीण् सीण् 271। उन्होंने यह भी कहा है कि गवाहों ने तथ्य को दबा दिया था

अभियुक्त व्यक्ति पर चोटों काए जिसका अर्थ था कि घटना की उत्पत्ति अनिश्चित और प्रतिकूल थी अभियोजन पक्ष के

ख् 2011

, 10 एसण् सीण् आर

मामले पर निष्कर्ष निकाला जाना था। तथ्यों के बारे में यह आग्रह किया गया है कि विचारण न्यायालय का अवलोकन कि घटना प्रभु के खेत में हुई थी गलत क्योंकि यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था कि यह था रघुवीर के साथ गिरवी रखा गया और यही कारण था कि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों के दौरान साक्ष्य के क्रम में रघुवीर सिंह ने खुद को भूमि पर पट्टेदार होने का दावा किया था न कि गिरवी रखने वाला जो यह उनके पहले के बयान से स्पष्ट रूप से अलग था। यह भी है इस बात पर जोर दिया गया कि उपरोक्त प्रस्तुतियों को इस तथ्य के साथ जोड़ा गया है कि घटनास्थल से शव बरामद नहीं किया गया था लेकिन मृतक के घर में पाया गया था और कि नहीं घटना स्थल से हल या खून उठाया गया था जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि घटना उस खेत में नहीं हुई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कहानी पेश की गई है पीडब्लू.1 द्वारा कि कल्लू ने पहली बार गिरधारी को अपने टैक्टर से ठोका था और फिर अपने ट्रैक्टर की लिफ्ट का उपयोग करते हुए ऊपर उठा दिया था खेती करने वाला और फिर उसे अपने शरीर पर गिरा दिया था उसका बयान ब्तण्च्ण्ब् की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया है। और पहली बार अदालत में आया था और इसलिए नहीं हो सका पर भरोसा किया। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि पीडब्लू.3 छोटे लालएघायल गवाहों में से एक और जांच अधिकारी पीडब्लू 17 समयदीन ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया था कि विवाद भूमि के संबंध में पक्षों के बीच एक परिणाम था दोनों समूहों के बीच अचानक लड़ाई और इस तरह उच्च न्यायालय का अवलोकन सबूतों के आधार पर पूरी तरह से उचित था।

5 ण् हम सबसे पहले दायर एक अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे के बारे में सुश्री मखीजा की प्रारंभिक प्रस्तुति पर विचार करते हैं। इसके पैराग्राफ 25 में कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रशंसनीय या संभव थाए तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए किसी आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। दोषमुक्त। यह इस प्रकार देखा गया हैः ष् निम्नलिखित कुछ परिस्थितियाँ हैं जिनमें शायद यह न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करना उचित होगाए लेकिन ये उदाहरणात्मक नहीं हैं संपूर्णः उच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से रघुबीर सिंह बनाम पर आधारित है।

; ;पद्ध राजस्थान राज्य और ओआरएस। ख् हरजीत सिंह बेदीए जे।,

तय किए गए कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके कानून का गलत दृष्टिकोण स्थितिय

; ;खद्ध उच्च न्यायालय का निष्कर्ष इसके विपरीत है अभिलेख पर साक्ष्य और दस्तावेजय

; ;पपपद्ध व्यवहार में उच्च न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण। सबूत के साथ स्पष्ट रूप से अवैध था जिसके कारण न्याय की घोर विफलता। ; ;पअद्ध उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है औरगलत कानून और तथ्यों के आधार पर अनुचित मामले का रिकॉर्डय इस न्यायालय को हमेशा उचित महत्व देना चाहिए और

; अद्ध उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार करना। यह न्यायालय इसमें अत्यंत अनिच्छुक होगा

; अपद्ध किसी मामले में हस्तक्षेप करना जब दोनों सत्र अदालत और उच्च न्यायालय ने एक आदेश दर्ज किया है दोषमुक्त करने का ष्। उपरोक्त उद्धरण का एक तरह से अवलोकन इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश को कम कर देता है। इसलिएए हमें देखना होगा कि क्या इस न्यायालय को ऊपर निर्धारित मापदंडों के आधार पर हस्तक्षेप करना चाहिए। सबसे पहले इसे ध्यान में रखना होगा। कि अभियुक्त पर लगी चोटों को इस रूप में नहीं समझाया गया था अभियोजन पक्ष के गवाह ने एक शब्द भी नहीं कहा कि वे कैसे उन्हें पीड़ा हुई थी। इस मामले मेंएबचाव वैध रूप से संदेह पैदा कर सकता है कि की उत्पत्ति घटना रहस्य में डूबी हुई थी और अभियोजन पक्ष ने कार्यवाही के एक हिस्से को दबा दिया था। यह सच हैए जैसा कि तर्क दिया गया है डॉण् मनीष सिंघवी द्वाराए कि एक पर प्रत्येक चोट अभियुक्त को अधिक विशेष रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ अभियुक्त को हुई सभी चोटें सरल प्रकृति की होती हैं। ; जैसा कि वर्तमान मामले मेंद्ध और मामले के तथ्यों को होना चाहिए संभावनाओं की प्रकृति पर मूल्यांकन किया गया। घटना की जांच उपरोक्त के आलोक मेंए हम पाते हैं कि वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों में चोटें मामले को समझाने की आवश्यकता थी क्योंकि एक गंभीर मामला है उस भूमि के कब्जे के बारे में विवाद जिसमें घटना हुई थी ऐसा हुआ थाए विशेष रूप से क्योंकि रघुवीर सिंह खुद के अनुसार कब्जे की प्रकृति के बारे में अनिश्चित थे अभिलेख पर बयान और पटवारियों ने भी चेतावनी दी थी कि शिकायतकर्ता पक्ष को भूमि में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। निस्संदेहए बड़ी संख्या में घायल गवाह हैंए जिनमें से कुछ गंभीर रूप से आहतए अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिएए लेकिन उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के प्रकाश में

कि के बारे में अनिश्चितता थी कब्जाए यह तथ्य अपने आप में अभियुक्त को रोक नहीं सकता है यह दावा करने से कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्लू.3 चोट्टे लालए घायलों में से एक गवाहों ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि झगड़ा अचानक हो गया था और प्रतिद्वंद्वी समूह थे दोनों कहते हैं कि वे भूमि बोएँगे। यह याचिका पीडब्लू.17 समयदीन के साक्ष्य द्वारा भी समर्थित हैए जाँच अधिकारीए जिन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पटवारियों के अनुसारए लड़ाई उस भूमि पर हुई थी जो हाल ही में गौगा और दल्लू के कब्जे में थी और यह कि भूमि के अधीन थी शिकायतकर्ता पक्ष का अधिकार। यह कथन इस प्रकार है अन्य गवाह विशेष रूप से पीडब्लू 1 रघुवीर सिंह के साक्ष्य के साथ भिन्नता के रूप में उन्होंने कहा कि वे थे लगभग 20 वर्षों से विचाराधीन भूमि का कब्जा। वहाँ घटना स्थल के बारे में भी संदेह है। मृत शरीर और किसान को पीडब्लू.1 के घर से बरामद किया गया थाए औरपीडब्लू.17 ने स्वीकार किया कि स्थल से कोई भी खून से सना हुआ मिट्टी नहीं उठाया गया था। भंवर सिंह के मामले में फैसला ;ऊपरद्ध लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह केवल के दायरे से संबंधित है आईण् पीण् सीण् की धारा 149 के तहत अपराध। तथ्यों के आलोक में जो ऊपर गिने गए हैंए यह देखा जाएगा कि उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि दोनों पक्ष युद्ध करने आए थेए उचित प्रतीत होती है क्योंकि यह साक्ष्य की सराहना पर एक मूल्यांकन है जिसे स्पष्ट रूप से गलत नहीं कहा जा सकता है ताकि इस न्यायालय के हस्तक्षेप को आमंत्रित किया जा सके। दण् गजानंद के मामले ;ऊपरद्ध में कहा गया है कि मामले को स्वतंत्र लड़ाई के दायरे में लाने के लिए दोनों पक्षों को हथियारबंद रघुबीर सिंह बनाम को लाना होगा।

राजस्थान राज्य और ओआरएस। ख् हरजीत सिंह बेदीए जे।, और युद्ध करने के लिए तैयार होना वर्तमान मामले में इस परिणाम के साथ लागू किया जाना चाहिए कि प्रत्येक अभियुक्त अपने लिए उत्तरदायी होगा व्यक्तिगत कार्य।

6 ण् इस पृष्ठभूमि के साथए अब हम अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए वैकल्पिक तर्क पर जाते हैं। यहां तक कि मामले को एक स्वतंत्र लड़ाई के रूप में स्वीकार करते हुएए चारों अभियुक्त उत्तरदाता अर्थात कल्लूए असदुद्दीनए मौज और रहमत कल्लू के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि वह ट्रैक्टर था ड्राइवर जिसने पहले गिरधारी को धक्का दिया थाए फिर चला गया था ट्रैक्टर ने किसान को उसके ऊपर से उठा दिया और फिर उसे उसके व्यक्ति पर गिरा दियाए जिससे उसकी तुरंत मौत हो

गईए जबकि अन्य तीन ने गिरधारी को भी उनके हथियारों से चोटें आईं। हमने इस अंक पर साक्ष्य को बहुत सावधानी से देखा है। दण् मृत शरीर पर पाई गई चोटों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

ष् 1 ण् बाईं ओर एल.एल ;टूमद्ध क्षेत्र में पीठ पर छिद्रित चोट पेरिटोनियल गुहा आकार 12 ग 5 सेमी ग पेरिटोनियम तक गहराई तक पीछे की ओर 9 मीटर 10 और 11 वीं पसली का फ्रैक्चर भी होता है।

3 ण् दाहिनी ओर नियमित रूप से 5 ग 1 ण्5 सेण् मीण् का घाव पेरीटो फ्रंटल क्षेत्र अनुप्रस्थ रूप से।

4 ण् सिर के बीच में 5 ग 1 ण्5 सेमी घाव दोनों पार्श्विका हड्डी अनुदैर्ध्य रूप सेए मार्जिन नियमित रूप से।

5 ण् घावः 2 बाएँ के बीच में ग 1 सेमी ग 0 ण्5 सेमी चिकित्सा पक्ष। चोटें प्रकृति और कारण में पूर्व.मृत्यु थीं मृत्यु प्लीहा की चोट के कारण रक्तस्राव और सदमे से हुई थी – चोट संख्या 1 से बाईं किडनी ष्। खेती करने वाले की चोट चोट संख्या 1 है जो घातक चोट है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट और गवाहों द्वारा इसका श्रेय कल्लू को दिया गया है। हालाँकिए सुश्री मखीजा ने तर्क दिया है कि जो कहानी पहले किसान के पास थी गिरधारी पर गिराए जाने और गिरधारी पर गिराए जाने पर विश्वास नहीं किया जा सका क्योंकि रघुवीर सिंह ने अपने साक्ष्य में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया था हालाँकि अन्य गवाहों ने ऐसा किया था और इस तरहए यह कहानी असंभव थी। हालांकिए यह मानते हुए कि एक कृषक के कारण हुई चोट संख्या 1 से स्पष्ट है चिकित्सा साक्ष्य और चोट की सीमा और गंभीरता से पता चलता है कि कल्लू का इरादा गिरधारी की मौत का कारण बनना था। यह भी है सबूत से स्पष्ट करें कि चोट संख्या 1 कारण बनने के लिए पर्याप्त थी प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु। चोटों के कारण ऊपर उल्लिखित अन्य तीन आरोपी सरल थे। प्रकृति में और कल्पना के किसी भी विस्तार सेए कहा जा सकता है मृत्यु का कारण बना। इस तथ्य के आलोक में कि हम एक स्वतंत्र लड़ाई के मामले से निपट रहे हैंए असदुद्दीनए मौज और रहमत को उनकी संबंधित चोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और वास्तव मेंए रहमत की मृत्यु तब हुई थी जब मामला उच्च न्यायालय में था। इसलिएए हमारी राय है कि जहाँ तक कल्लू प्रत्यर्थी का संबंध हैए धारा के तहत उसकी दोषसिद्धि 304 उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर भी आईण् पीण् सीण् का भाग प्प् गलत था। हमए तदनुसारए इन अपीलों की अनुमति देते हैं . इस हद तक कि कल्लू को आईण् पीण् सीण् की धारा 303 के तहत दोषी ठहराया गया है। गिरधारी की हत्या

का कारण बनने के लिए और हम निचली अदालत के फैसले को इस सीमित सीमा तक बहाल करते हैं। जहाँ तक अन्य अभियुक्त संबंधित हैंए अपील खारिज कर दी जाती हैं।

7 ण् न्यायमित्र का शुल्क 7 ए 000 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रत्येक अपील। अपीलों की अनुमति दी गई।

डी जी।

नोट :– यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल ''सुवास'' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जमीर हुसैन सैयद (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।